श्री ओम् मेहता (जम्मू तथा काश्मीर): हम हरियाणा और दिल्ली दोनों के चौधरी के दर्मियान में हैं ।

डा० भाई महावीर : दर्मियान में नहीं त्रिकोण में हैं । श्रीमन्, नवम्बर, 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था उस वक्त 3 डैम बन रहे थे—व्यास-सतलज लिंक प्रोजेक्ट, व्यासडैम और भाखड़ा डैम । इन तीनों में 5,000 के करीब श्रमिक काम कर रहे थे । जो पंजाब का रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट पास हुआ उसकी धारा 80 और 82 के अनुसार ये जो श्रमिक काम कर रहे थे, उनको अपने-अपने निवास के राज्य को एलोकेट किया जाना था । इसके अनुसार बाकियों का तो हो गया है, लेकिन 5,000 में से 600 ऐसे कर्मचारी रह गये हैं जो हिमाचल प्रदेश के निवासी होने के बावजूद उनको हिमाचल प्रदेश में लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार राजी मालूम नहीं होती और यहां तक हुआ है कि पंजाब हाई कोर्ट में तलवाड़ा डैम, व्यास डैम के श्रमिक रिट् पेटीशन लेकर गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारे श्रमिकों को, जिस राज्य के वे निवासी हैं, उसी में एलोकेट करने के लिये कदम उठाए जाएं । तीनों रा यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा—की एक मीटिंग हुई जुलाई, 1971 में और उसमें मेरी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने यह स्वीकार कर लिया कि इन 600 श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मन बदल लिया । मालूम होता है और उनको पंजाब या हरियाणा की तरफ भेजने का यत्न किया जा रहा है । मेरा अपना आग्रह है और सरकार से निवेदन है कि यह एक मानवीय पहलू है कि 600 लोग जिनके घर हिमाचल प्रदेश में हैं, वे चाहते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई अपने उस वायुमण्डल में हो और वे वही पढ़ें जो उनके क्षेत्र में पढ़ाया जाता है और और स्वयं उनके दो जगह घरबार न हों और उससे मंहगाई से भी वे बच सकेंगे, यदि उनको हिमाचल प्रदेश की तरफ एलोकेट किया जाए । इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब के रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट की धारा 80 और 82 के अनुसार केन्द्रीय सरकार उनको हिमाचल प्रदेश में ही एब्जार्व किए जाने का आदेश दे या एक परामर्श दे और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बारे में उचित कदम जल्दी उठाए ।

REFERENCE TO POWER CRISIS IN PUNJAB

श्रीमती सीता देवी (पंजाब): माननीय उप-सभापति जी, मैं एक बहुत आवश्यक विषय के ऊपर आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं । आपको पता है कि आजकल वर्षा न होने से पावर की बड़ी शार्टेज है । वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के ऊपर ही इसका प्रभाव है, पर पंजाब के ऊपर विशेष प्रभाव है । पंजाब में इस वक्त गोविन्द सागर में जितना पानी होना चाहिए था उसका 50 परसेन्ट है और ऐसी आशंका हो रही है कि अगर यही हालत रही तो अगले 2 साल तक पंजाब में बड़ी भारी क्राइसिस बिजली की आने वाली है । हम 75 लाख यूनिट बिजली भाखड़ा से लेते थे, जिससे हमारा एग्रिकलचर, हमारी इन्डस्ट्री और हर चीज चलती थी । आपको पता है कि पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन किस प्रकार हुआ और ग्रीन रिवोल्यूशन का क्रेडिट पंजाब सरकार को भी है, पंजाब के एग्रिकल्चरिस्ट के मेहनत को भी है और पावर वगैरह उसको मिलती रहे तो काम भी ज्यादा अच्छा होता है । तो हम 75 लाख यूनिट बिजली भाखड़ा से लेते थे, वह इस वक्त हमें 32 लाख भाखड़ा से और 20 लाख जोगेन्द्रनगर के थर्मल प्लान्ट से मिला कर मिलती है । तो 23 लाख यूनिट की हमें प्रतिदिन की शार्टेज है । तो आप बताएं कि किस तरह से इतने में पंजाब का काम चल सकता है । पंजाब में 40 परसेन्ट "कट" सारे अर्बन एरिया पर लगा दिया है और एग्रिकलचर वाले जिनको 24 घण्टे पानी मिलता था, अब सिर्फ 4 घंटे उनको बिजली दे रहे हैं । आप अंदाजा करें कि 4 घंटे बिजली देने से एग्रिकलचर की क्या हालत होगी । सारा एग्रिकलचर सूख रहा है ।

[श्रीमती सीता देवी]

खत्म हो रा है । रबी की फसल बिलकुल ही खत्म हो गई है ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : ऐसी हालत हरियाणा में भी है ।

श्रीमती सीता देवी : आप दूसरों की बात में क्यों बोलते हैं ? और इन्डस्ट्री की इतनी बुरी हालत है । मैं आपको बताती हूं, पंजाब बार्डर में है । अभी लड़ाई हुई थी तो पंजाब ने कितना सफर किया । पंजाब के बार्डर के स्माल सेक्टर इन्डस्ट्री वालों ने, वहां के रहने वाले मजदूरों ने इतना सफर किया । अब हम सिर्फ हफ्ते में 4 दिन इण्डस्ट्री को बिजली दे रहे हैं । उसके क्या परिणाम हो रहे हैं ? जहां पर इण्डस्ट्री की तबाही हो रही है, स्माल स्केल इण्डस्ट्री खत्म हो रही है वहां जो मजदूर हैं, जिसने लड़ाई के दौरान इतना सफर किया, उसमें बहुत अन्इम्प्लायमेंट फैल रहा है । इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं अपने भारत सरकार का.

श्री उपसभापति : अब खत्म कीजिए ।

श्रीमती सीता देवी : मैं सुझाव देना चाहती हूं । दो-तीन तरह के सुझाव देना चाहती हूं । एक तो जो नंगल फर्टिलाइजर है उनको जितनी बिजली मिलती है, अगर हम कुछ देर के लिए फर्टिलाइजर के लिए बिजली बन्द भी कर दें, तो भी गुजारा हो सकता है । मैं भी समझती हूं कि फर्टिलाइजर की भी नेसेसिटी है, उसको हम बिलकुल बन्द तो नहीं कर सकते, अगर हम उनको जितनी बिजली देते थे उसमें से आगे भी गुजारा करें, 29 लाख यूनिट्स में से 14 लाख यूनिट्स आप पंजाब को दे सकते हैं जो कि उनको एक्स्ट्रा दी गई है । उसके बिना आगे भी नंगल फर्टिलाइजर चलता था और अब भी चल सकता है ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है, वहां से आप हमें पावर दे सकते हैं । हमने आज ही पेपर में पढ़ा है कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं पंजाब के उनसे डिसकस भी किया है और कुछ आश्वासन भी दिया है ।

मेरा एक और सुझाव है कि दिल्ली को जो भाखड़ा से बिजली मिलती है, डी० ई० एस० यू० को, ठीक है मैं यह नहीं कहती कि बहुत कम कर दी जाए, लेकिन मैं यह जरूर कहती हूं कि जो अनप्रोडक्टिव परपज के लिए बिजली है उस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जैसे इन्डस्ट्री है वह चलनी चाहिए, एग्रिकलचर चलना चाहिए, मगर जैसे एयर कंडीशनिंग है या जो सड़कों पर, चौराहों पर सजावट है—आप कैनाट प्लेस को ही देख लीजिए—वहां पर जो बिजली जगमगाती है, ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए । जिस वक्त मुल्क में सूखा पड़े और हमारे पंजाब में इतनी बुरी हालत हो, तो मैं समझती हूं इन चीजों में "कट" लगना चाहिए, एयरकंडीशनिंग के बिना हम रह सकते हैं । (*Time bell rings*) मैं समझती हूं दिल्ली में जो बिजली अनप्रोडक्टिव परपज के लिए खर्च हो रही है उसके ऊपर कट लगाना चाहिए और पंजाब को बचाना चाहिए ।

अन्त में मैं प्रार्थना करती हूं कि जो आपने कोटा लगाया है हरियाणा और पंजाब का, उसमें आपने बताया 66 लाख में से मेजर पोर्शन पंजाब ने दिया, क्योंकि पंजाब सारे हिन्दुस्तान को फीट करता है । इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ।

REFERENCE TO RESIGNATION BY CHAIRMAN AND OTHERS OF FERTILIZER CORPORATION OF INDIA

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the serious situation that the top bureaucrats of this country have brought about in the Fertilizer Corporation of India. The Fertilizer Corporation of India is one of the most important public undertakings in the country and its functioning and production of fertilizer is very essential for the country. A situation has been created by the bureaucrats in which the wholetime Directors and the Chairman of the Corporation, Dr. Sethna, an eminent scientist have all resigned *en bloc* because of the interference off and onby the Committee of Manafgernent on which there are four ICS Secretaries headed by the Secretary of Mines.